

सम्पूर्ण-संक्षिप्त-समर्थ

CURRENT AFFAIRS गुरु

UPSC/State PSC परीक्षा की तैयारी करने वाले हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए



29th AUGUST 2022



FOR DAILY FREE CURRENT AFFAIRS
Follow Our Youtube Channel

 Guru Deekshaa Hindi



INDEX

DAILY CURRENT AFFAIRS NOTES

29th August 2022

1. - डिजिटल इंडिया के बारे में:	3
(i) डिजिटल इंडिया विजन के मूल मूल्य हैं:	3
(ii) उद्देश्य:	3
(iii) विभिन्न डिजिटल इंडिया कार्यक्रमों की योजनाएँ:	3
(iv) महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ:	3
(v) अगले कदम:	4
2. - भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का विवरण:	5
(i) परिचय:	5
(ii) सीएजी कार्यालय के लिए संवैधानिक शर्तें:	5
(iii) अपॉइंटमेंट, समय-सीमा और निष्कासन:	5
(iv) सीएजी की स्वतंत्रता की गारंटी और बचाव के लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गए हैं:	5
(v) सीएजी की निष्पक्षता:	6
(vi) रिपोर्ट:	6
(vii) पीएसी और सीएजी के संबंध में:	6
(viii) सीएजी की चिंताएं:	7
(ix) सीएजी रिपोर्ट में कटौती और देरी:	7
(x) आवश्यक सुधार:	7
(xi) कैग की प्रभावशीलता को कैसे बढ़ाया जाए:	8
(xii) निष्कर्ष:	8
3. - पीएम केयर्स फंड के बारे में:	9
(i) PM-CARES फंड का तंत्र क्या है?	9
(ii) PM-CARES फंड किन समस्याओं से निपट रहा है?	9



4. - ड्रैगन फ्रूट की खेती का विवरण:.....	11
(i) परिचय:	11
(ii) विशेषताएँ:	11
(iii) भारत में अनुकूलता:.....	11
(iv) संबंधित चिंताएं:	11
(v) सरकारी कार्यक्रम:	12

संपादकीय विश्लेषण..... 13

1. भारत में गरीबी:.....	13
(i) गरीबी: यह क्या है?	13
(ii) भारत की गरीबी को कैसे मापा गया?	13
(iii) स्वतंत्र भारत की गरीबी दर का अनुमान है:	13
(iv) भारत की गरीबी की जड़ क्या है?	15
(v) अभी क्या स्थिति है?	16
(vi) मध्यम वर्ग:	17
(vii) कम आय वाला समूह:.....	17
(viii) विशेषाधिकार के साथ जनसंख्या:	17
(ix) कारण:	17
(x) गरीबी की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?	17
(xi) महामारी के बाद की पहल:.....	19
(xii) आगे कैसे जारी रखें:	19

2. भारत में सभी मुफ्त सुविधाओं के बारे में:.....	20
(i) फ्रीबीज क्या दर्शाता है:.....	20
(ii) मुफ्त चीजों का क्या औचित्य है?.....	20
(iii) मुफ्त चीजों में क्या कमियां हैं?	21
(iv) अगले कदम:	21



1. - डिजिटल इंडिया के बारे में:

जीएस II

विषय → सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

डिजिटल इंडिया विजन के मूल मूल्य हैं:

- डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सभी नागरिकों के लिए एक संसाधन है।
- ऑन-डिमांड सेवाएं और शासन।
- नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण

उद्देश्य:

- भारत को ज्ञान आधारित भविष्य के लिए तैयार करने के लिए।
- यह महसूस करते हुए कि आईटी आईटी प्लस आईटी (भारतीय प्रतिभा) (सूचना प्रौद्योगिकी) का परिणाम होगा
- परिवर्तन का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना।

विभिन्न डिजिटल इंडिया कार्यक्रमों की योजनाएँ:

- ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, या दीक्षा पहल
- यह देश के शैक्षिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के रूप में कार्य करता है। नवीनतम डिजिटल तकनीक देश के प्रत्येक शिक्षक के लिए उपलब्ध होगी।

- eNAM: यह अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसे 14 अप्रैल, 2016 को पेश किया गया था, सभी राज्यों की कृषि उपज बाजार समितियों (APMCs) को जोड़ता है।
- eSanjeevani स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित टेलीमेडिसिन सेवा मंच का ब्रांड नाम है।
- DigiBunai: DigiBunai बुनकरों को साड़ी के डिजाइन को करघे के अनुकूल फाइलों में बदलने और डिजिटल कलाकृति बनाने में सक्षम बनाता है।
- प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मा निर्भर निधि (पीएम स्वानिधि) परियोजना को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को कम-ब्याज ऋण की पेशकश करने के लिए शुरू किया गया था। यह स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेनदेन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- संपर्क अनुरेखण कार्यक्रम आरोग्य सेतु कोविड -19 द्वारा सुझाए गए डिजिटल समाधानों में से एक था।
- कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम, जैसे भारतनेट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया, औद्योगिक गलियारे, आदि, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से उपलब्ध हैं।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ:

- उन्नत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान: UPI की शुरुआत ने डिजिटल भुगतान को पूरे देश में और अधिक लोकप्रिय बना दिया।
- भुगतान और लेन-देन में UPI की सहायता से प्रमुख उद्यमों से लेकर स्वतंत्र रेहड़ी-पटरी वालों तक सभी को लाभ होता है।



- इसके अतिरिक्त, यह अन्य निजी अभिनेताओं को डिजिटल भुगतान के विकल्प की पेशकश करने के लिए प्रेरित करता है, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी हद तक बदल दिया है।
- सरलीकृत व्यावसायिक प्रक्रियाएं: व्यवसायों को उनके संचालन को सुव्यवस्थित करने में सहायता करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक ग्राहक पहचान प्रणाली (ई-केवाईसी), इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ भंडारण प्रणाली (डिजिलॉकर), और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रणाली (ई-साइन) विकसित की गई।
- JAM ट्रिनिटी और बियाँड द JAM ट्रिनिटी- जन धन, आधार और मोबाइल- को शुरू में सिस्टम लीकेज को रोकने के लिए चालू किया गया था। पूरे कोविड प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत इसी एक छोटी सी कार्रवाई से हुई, जिससे भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद एकमात्र ऐसा देश बन गया, जिसने 20 करोड़ कोविड-19 जैक्स का प्रशासन किया।

अगले कदम:

- कराधान चुनौतियों, सीमित बुनियादी ढांचे, खराब इंटरनेट, विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग की कमी और डिजिटल निरक्षरता सहित कई तरह की समस्याएं इसके उचित कार्यान्वयन में बाधक हैं। इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए कई चुनौतियों से पार पाना होगा।
- यहां छह विशिष्ट कदम दिए गए हैं जो भारत को नया डिजिटल बेंचमार्क बनने में मदद कर सकते हैं क्योंकि हम डिजिटल इंडिया के लॉन्च के छह साल पूरे कर रहे हैं। भारत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और पांच ट्रिलियन

डॉलर जीडीपी तक पहुंचने में मदद करने के लिए 4.0 का उपयोग कर रहा है।

- एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना जिसमें धारणा के संबंध में निर्णय किए जाते हैं।
- गैजेट की कम कीमतें और डेटा तक आसान पहुंच, विशेष रूप से स्मार्टफोन के लिए।
- त्वरित प्रौद्योगिकी और निरंतर कनेक्टिविटी (5G, 6G)।
- स्थानीय भाषा में उच्च क्षमता वाली जानकारी।
- लोकपाल, शिकायत प्रतिनिधित्व और विवाद समाधान के लिए एक समर्पित वातावरण जो ऑनलाइन सुरक्षित और सुरक्षित है।
- अंत में, अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी और अधिक एजेंसियां एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगी। भरपूर मात्रा में बिजली, हरित प्रौद्योगिकियां, और नवीकरणीय ऊर्जा
- डिजिटल इंडिया की बदौलत एग्रीटेक, हेल्थ टेक, स्मार्ट सिटीज, ई-गवर्नेंस, रिटेल मैनेजमेंट और साधारण बैंकिंग और पेमेंट सॉल्यूशंस अब लागू किए जा सकते हैं, जो सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है।

• स्रोत→ इंडियन एक्सप्रेस



2. - भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

का विवरण:

जीएस II

विषय→विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति

परिचय:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को एक स्वायत्त कार्यालय (CAG) के रूप में नामित करता है।
- वह भारत की सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के स्तंभों में से एक हैं और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अध्यक्ष हैं।
- वह सार्वजनिक पर्स के रक्षक के रूप में संघीय और राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली की देखरेख के प्रभारी हैं।
- वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में, वह भारतीय संविधान और संसदीय नियमों का सम्मान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

सीएजी कार्यालय के लिए संवैधानिक शर्तें:

- अनुच्छेद 148 सीएजी की नियुक्ति, शपथ और जिम्मेदारियों का एक सामान्य अवलोकन प्रदान करता है।
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और अधिकार अनुच्छेद 149 के अंतर्गत आते हैं।
- अनुच्छेद 150 के अनुसार, राष्ट्रपति सीएजी के सुझावों के आधार पर संघ और राज्य के खातों के लिए एक प्रारूप स्थापित कर सकते हैं।

- राष्ट्रपति के अनुरोध पर, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संसद के प्रत्येक सदन को संघ के वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट प्रदान करेंगे।
- धारा 279: भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक "शुद्ध आय" की गणना को निर्धारित और प्रमाणित करता है और उसका प्रमाण पत्र निश्चित है।

अपॉइंटमेंट, समय-सीमा और निष्कासन:

- भारत के राष्ट्रपति एक वारंट पर हस्ताक्षर करते हैं और उस पर मुहर लगाते हैं जिसमें सीएजी का नाम होता है।
- सीएजी उस क्षमता में तब तक काम करेगा जब तक कि वे 65 वर्ष की आयु तक या छह वर्ष की अवधि तक नहीं पहुंच जाते, जो भी पहले हो।
- वह राष्ट्रपति को पत्र भेजकर जब चाहें इस्तीफा देने के लिए स्वतंत्र हैं।
- उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्याय के समान औचित्य और प्रक्रियाओं का उपयोग करके पद से हटाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति के पास उसे अपदस्थ करने की शक्ति है यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का एक विशेष बहुमत के साथ एक प्रस्ताव पारित करते हैं, या तो सिद्ध दोष या अक्षमता के आधार पर।

सीएजी की स्वतंत्रता की गारंटी और बचाव के लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गए हैं:

- वह एक सुरक्षित कार्यकाल का आनंद लेता है और उसे केवल राष्ट्रपति के अधिकार और संविधान में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुपालन में हटाया जा सकता है। इसलिए वह औपचारिक रूप से तब तक पद पर नहीं हैं जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा चुने जाने के बावजूद राष्ट्रपति उन्हें ऐसा घोषित नहीं करते।



- अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ने के बाद, वह भारत सरकार या किसी भी राज्य के साथ किसी अन्य नियुक्ति के लिए अपात्र है।
- संसद उनके वेतन और अन्य सेवा आवश्यकताओं को निर्धारित करती है। उनका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश के बराबर है।
- उनकी नियुक्ति के बाद, न तो उनका वेतन और न ही अनुपस्थिति की छुट्टी, पेंशन, या सेवानिवृत्ति की आयु के उनके अधिकारों को नकारात्मक रूप से बदला जा सकता है।
- भारत की समेकित निधि का उपयोग सीएजी के कार्यालय की प्रशासनिक लागतों को कवर करने के लिए किया जाता है, जिसमें सभी कर्मचारी वेतन, लाभ और पेंशन शामिल हैं। संसद को इन लागतों को मंजूरी देने की जरूरत नहीं है।
- संसद (दोनों सदनों) में, कोई भी मंत्री सीएजी की ओर से नहीं बोल सकता है या उसके किसी भी कार्य पर पूछताछ नहीं की जा सकती है।

सीएजी की निष्पक्षता:

- भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि, और एक विधान सभा के साथ संघ शासित प्रदेश सभी के खातों की सीएजी द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है।
- भारत के लोक लेखा, भारत की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा और आकस्मिकता निधि के लिए, सभी व्ययों की लेखा परीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।
- केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग द्वारा बनाए गए सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि, बैलेंस शीट और अन्य सहायक खातों की लेखा परीक्षा केंद्रीय लेखा समूह (CAG) द्वारा की जाती है।

- सरकारी निगमों के साथ-साथ अन्य निगमों और निकायों के पास अपने राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षण सीएजी द्वारा किया जाता है जैसा कि लागू कानूनों द्वारा आवश्यक है। यह उन सभी निकायों और प्राधिकरणों पर भी लागू होता है जो प्राथमिक रूप से केंद्रीय या राज्य के संसाधनों से वित्त पोषित होते हैं।
- किसी भी कर या शुल्क का शुद्ध राजस्व उसके द्वारा निर्धारित और प्रमाणित किया जाता है, और उसका प्रमाणीकरण इस मामले में निर्णायक होता है।

रिपोर्ट:

- राष्ट्रपति और राज्यपाल केंद्र और राज्य के खातों पर अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करते हैं, और वे उन्हें क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल के सदनों में पहुंचाते हैं।
- तीन ऑडिट रिपोर्ट- एक वित्तीय खातों पर, एक सार्वजनिक उपक्रमों पर, और एक विनियोग खातों पर- उनके द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है।

पीएसी और सीएजी के संबंध में:

- वह संसद के संरक्षक, मित्र और दार्शनिक की लोक लेखा समिति के रूप में कार्य करता है।
- पीएसी जिन तीन सीएजी रिपोर्टों पर गौर करती है, उनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्त खातों और विनियोग खातों पर ऑडिट रिपोर्ट शामिल हैं।
- उन मुद्दों की सूची जिन पर पीएसी के तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, एक और तरीका है जिससे सीएजी समिति की बहस में योगदान देता है।



- इसके अतिरिक्त, वह समिति और सरकार के संबंधित कार्यों को समझने में समिति और गवाहों की सहायता करता है।
- कभी-कभी, सीएजी की भूमिका एक दुभाषिया और अनुवादक की होती है, जो राजनेताओं को अधिकारियों की राय और इसके विपरीत बताता है।
- सीएजी अभी भी अन्य मुद्दों के लिए जिम्मेदार है। उसे अपने द्वारा सुझाए गए उपाय के कार्यान्वयन पर नजर रखनी चाहिए। जब उसे पता चलता है कि कुछ नहीं किया गया है, तो वह मामले को पीएसी के ध्यान में लाता है।

सीएजी की चिंताएं:

इसके लिए कोई निर्धारित मानक नहीं हैं:

- यदि शर्तों को स्पष्ट किया जाता है, तो स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सकती है। इस तरह के मानदंड में सीएजी के साथ-साथ चयन प्रक्रिया के रूप में चुने जाने के लिए एक उम्मीदवार के गुण शामिल होंगे। प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है।

दुर्गमता मुद्दा:

- वर्तमान में, वित्त मंत्री कैबिनेट सचिव को एक शॉर्टलिस्ट भेजता है, जो फिर प्रधान मंत्री की ओर से सीएजी का चयन करता है।
- इस सूची में से एक उम्मीदवार की सिफारिश प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। यदि राष्ट्रपति सहमत होते हैं, तो सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर वाले वारंट द्वारा की जाती है।
- ऐसी तकनीक त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इसमें हितों का टकराव हो सकता है।

समझौता जवाबदेही:

- भारत सरकार, जिसका नेतृत्व प्रधान मंत्री करते हैं, CAG द्वारा लेखा-परीक्षा की जाती है।
- ऐसी संभावना है कि लेखापरीक्षिता के बॉस द्वारा अपनी कंपनी का लेखा-जोखा करने के लिए चुना गया व्यक्ति अंततः सीएजी बन जाएगा, जिससे जवाबदेही कम हो सकती है।

सीएजी रिपोर्ट में कटौती और देरी:

- नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में देरी होने और अब लंबित होने के बाद से आलोचक इसे "CAGed" के रूप में संदर्भित करते हैं।
- सूचना के अधिकार (आरटीआई) के अनुरोध पर हाल ही में प्रतिक्रिया के अनुसार, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों को संदर्भित करने वाली सीएजी रिपोर्टों की कुल संख्या 2015 में 55 से घटकर 2020 में सिर्फ 14 रह गई, जो 75% से अधिक का नुकसान है।

आवश्यक सुधार:

स्वतंत्रता की स्थापना:

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान का प्रमुख स्वतंत्र रूप से संचालित होता है और कार्यकारी से प्रभावित नहीं होता है, जिसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने पर ऑडिट राय देने की आवश्यकता होती है, अधिकांश देशों ने कुछ योग्यताओं को स्थापित करने वाले कानून पारित किए हैं। साथ ही नियुक्ति की प्रक्रिया।



- यूके के राजकोष और लेखा परीक्षा अधिनियम के 1983 के संशोधन के अनुसार, सीएजी को प्रधान मंत्री और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाएगा, और बाद में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी। नियुक्ति में गोपनीयता:
- भारत को सीएजी नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक औपचारिक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।
- इन मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदकों की सूची तैयार की जा सकती है। फिर, एक उच्च-स्तरीय समिति उम्मीदवारों के व्यक्तित्व का आकलन कर सकती है और राष्ट्रपति को तीन उम्मीदवारों की एक सूची सुझा सकती है, जिसमें से केवल एक का चयन किया जा सकता है।

देरी से छुटकारा:

- एक महीने के भीतर सूचना प्राप्त करने के लिए 2005 के आरटीआई अधिनियम के तहत नागरिक के अधिकार के समान, लेखा परीक्षकों को सात दिनों के भीतर दस्तावेजों तक प्राथमिक पहुंच होनी चाहिए; यदि नहीं, तो विभागाध्यक्षों को विलम्ब के लिए तर्क प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होना चाहिए।

प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे थे। सम्मेलन ने सार्वजनिक लेखा परीक्षा के ज्ञान को बढ़ाने के लिए राष्ट्रमंडल देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया।

- तथ्य यह है कि भारतीय सीएजी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का ऑडिट करने में सक्षम था, जिसमें कई जटिल कार्य शामिल हैं, संगठन की विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है।

निष्कर्ष:

- सीएजी कार्यालय में सुधार महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे संसद और राज्य विधानसभाओं को अपने संबंधित प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने में सक्षम बनाते हैं।
- वह भारत की लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के स्तंभ के रूप में कार्य करता है और बीआर अम्बेडकर के शब्दों में, भारतीय संविधान के तहत अनुमत सबसे महत्वपूर्ण स्थिति में है।

• स्रोत → हिन्दू

कैग की प्रभावशीलता को कैसे बढ़ाया जाए:

- बिग डेटा प्रबंधन रणनीति का सीएजी का प्रकाशन और दिल्ली में डेटा प्रबंधन और विश्लेषिकी केंद्र का निर्माण बिग डेटा क्रांति के बाद सकारात्मक विकास के उदाहरण हैं।
- 2017 राष्ट्रमंडल महालेखा परीक्षक सम्मेलन भारत के सीएजी में आयोजित किया गया था। दो सम्मेलन विषय सार्वजनिक लेखा परीक्षा और पर्यावरण लेखा परीक्षा में



3. - पीएम केयर्स फंड के बारे में:

जीएस II

विषय → सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

➤ संदर्भ:

- केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के एक फैसले के अनुसार, आयकर विभाग को आयकर अधिनियम के तहत छूट के लिए आवेदन करते समय पीएम केयर्स फंड की हर फाइल की प्रतियां जारी करने का आदेश दिया गया था। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश पर फांसी पर रोक लगा दी।

PM-CARES फंड का तंत्र क्या है?

- COVID-19 के प्रकोप जैसी कठिन परिस्थितियों का जवाब देने के लिए, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत कोष, या PM CARES फंड, की स्थापना मार्च 2020 में की गई थी।
- फंड को कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है; सभी योगदान स्वैच्छिक हैं और व्यक्तियों और संगठनों दोनों से उत्पन्न होते हैं।
- दान का उपयोग अब कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन वे अब कर कटौती योग्य नहीं हैं।
- इसके अलावा, यह 2010 के अंतर्राष्ट्रीय योगदान (विनियमन) अधिनियम से मुक्त है और बाहर से योगदान लेता है, इस तथ्य के बावजूद कि केंद्र ने पहले केरल बाढ़

जैसी तबाही के मद्देनजर विदेशी सहायता को ठुकरा दिया था।

- प्रधानमंत्री निधि के आधिकारिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और संबंधित व्यवसायों में तीन प्रसिद्ध व्यक्तियों के न्यासी बोर्ड को सिफारिश कर सकता है।
- निधि के पदेन न्यासी के रूप में, रक्षा, गृह मामलों और वित्त मंत्री सेवा करते हैं।

PM-CARES फंड किन समस्याओं से निपट रहा है?

- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) जैसे अन्य फंडों की उपेक्षा करता है।
- पीएम केयर्स फंड भारतीय संविधान या किसी अन्य कानून के अनुरूप स्थापित नहीं किया गया था, प्रधानमंत्री के शीर्षक, राष्ट्रीय प्रतीकों, आधिकारिक पीएमओ वेबसाइट (gov.in), एक आदेश के माध्यम से कर छूट का उपयोग करने के अधिकार के बारे में चिंताओं को उठाते हुए, और बाकी चीजें।
- पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में सवाल हैं क्योंकि यह जो पैसा इकट्ठा करता है उसका सीएजी द्वारा ऑडिट नहीं किया जाता है और यह भारत के समेकित कोष में नहीं जाता है।
- ट्रस्ट का प्रबंधन संघीय सरकार और राज्य सरकारों से स्वतंत्र है।
- यदि PM CARES फंड सरकार से संबद्ध नहीं है, तो यह एक लाभकारी संगठन बन सकता है, जो प्रधानमंत्री और तीनों मंत्रियों को अपने-अपने संवैधानिक पदों को बनाए रखने से रोकेगा।



- चूंकि ट्रस्टियों को ट्रस्ट की संपत्ति के बारे में जानकारी के साथ लाभार्थियों को प्रदान करने के लिए भारतीय ट्रस्ट अधिनियम की धारा 19 द्वारा आवश्यक है, पीएम केयर्स फंड आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अनुसार उपलब्ध होना चाहिए।
- थलप्लम सर्विस कॉप के अनुसार, यह निर्धारित करने का एक कारक है कि क्या कोई संगठन आरटीआई अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में योग्य है या नहीं। बैंक लिमिटेड बनाम केरल राज्य का मामला।
- फंड के बारे में हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आरटीआई द्वारा पीएमओ की आवश्यकता होती है क्योंकि यह एक सार्वजनिक संस्था है।
- **स्रोत→ इंडियन एक्सप्रेस**

GURU DEEKSHAA IAS



4. - ड्रैगन फ्रूट की खेती का विवरण:

विशेषताएँ:

प्रीलिम्स विशिष्ट विषय

➤ संदर्भ:

- चूँकि ड्रैगन फ्रूट को इसके कई स्वास्थ्य लाभों के लिए "सुपर फ्रूट" माना जाता है, इसलिए केंद्र ने इसके विकास का समर्थन करने के लिए चुना है। यह फैसला गुजरात और हरियाणा की सरकारों की नीति के अनुरूप है। केंद्र का मानना है कि भारत में इसकी पहुंच और इसके पोषण लाभों के कारण विश्व स्तर पर इसकी उच्च मांग को देखते हुए भारत में फल का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यह विदेशी फल, जो वर्तमान में 3,000 हेक्टेयर में उगाया जाता है, पांच वर्षों में 50,000 हेक्टेयर तक फैल जाएगा।

परिचय:

- अमेरिका वह जगह है जहां ड्रैगन फ्रूट पहली बार दिखाई दिया (हायलोसेरस अंडेटस)। यह कैक्टस परिवार से संबंधित है।
- इसे विश्व स्तर पर "पिटाया," "पिथाया," स्ट्रॉबेरी नाशपाती, रईस और रात की रानी के रूप में भी जाना जाता है। इसे भारत में "कमलम" भी कहा जाता है।
- यह विभिन्न प्रकार की जलवायु परिस्थितियों और मिट्टी के प्रकारों में पनपता है, खासकर भारत के अर्ध-शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों में।
- हालांकि यह मिट्टी में कुछ लवणों का सामना कर सकता है, यह थोड़ी अम्लीय मिट्टी से प्यार करता है।
- भारत में ड्रैगन फ्रूट के पेड़ मानसून के मौसम (जून से नवंबर) के दौरान फूल और फल लगते हैं।

- इसके फूल रात में खुलते हैं और स्वभाव से उभयलिंगी होते हैं (जिसमें नर और मादा दोनों अंग होते हैं)।
- संयंत्र की उपज 20 से अधिक वर्षों तक चलती है, उन उद्योगों के लिए फायदेमंद है जो प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य जोड़ते हैं, और न्यूट्रास्युटिकल विशेषताओं (जिनके चिकित्सीय प्रभाव हैं) में प्रचुर मात्रा में है।
- कई विटामिन और खनिज हैं।

भारत में अनुकूलता:

- 1990 के दशक में, भारत में पिछवाड़े के बगीचों में ड्रैगन फ्रूट को शामिल करना शुरू किया गया था।
- भारत का कृषक समुदाय इसकी कम रखरखाव आवश्यकताओं और उच्च लाभप्रदता के कारण ड्रैगन फ्रूट्स की ओर आकर्षित हुआ है।
- नतीजतन, कई उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ-साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ड्रैगन फ्रूट की खेती में तेजी से वृद्धि हुई है।
- प्रत्येक वर्ष, राष्ट्र लगभग 12,000 टन फल का उत्पादन करता है।

संबंधित चिंताएं:

- उच्च लागत: ड्रैगन फ्रूट की चढ़ाई क्षमता के कारण, उत्पादकों को लगभग रु। का निवेश करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में 3.5 लाख प्रति एकड़।
- ड्रिप इरिगेशन से शुरुआती खर्च में भी इजाफा होता है।



- अर्ध-शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में, धूप की कालिमा एक आम समस्या है जिसे 25-30% छाया बनाकर नियंत्रित किया जा सकता है, या तो छाया पैदा करने वाले पेड़ (जैसे मोरिंगा, सेसबानिया और मेलिया दूबिया) या छाया जाल लगाकर नियंत्रित किया जा सकता है। भीषण गर्मी के महीनों के दौरान।

सरकारी कार्यक्रम:

- बागवानी के एकीकृत विकास पर मिशन के माध्यम से, महाराष्ट्र सरकार ने कई राज्य क्षेत्रों में ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए गुणवत्ता रोपण सामग्री और इसके विकास के लिए वित्तीय सहायता (एमआईडीएच) प्रदान करके पहल की है।
- केंद्र समर्थित MIDH पहल पूरे बागवानी उद्योग को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। बांस, नारियल, काजू, जड़ और कंद, मशरूम, मसाले, फूल और सुगंधित पेड़ उगाना इसका एक उदाहरण है।
- 2014-15 से शुरू होकर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय MIDH को लागू करेगा।
- स्रोत→ डाउन टू अर्थ पत्रिका



संपादकीय विश्लेषण

1. भारत में गरीबी:

गरीबी: यह क्या है?

- 1990 के दशक से पहले, जब भारत में एक बंद अर्थव्यवस्था थी, इसके सभी निवासियों के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक संसाधनों तक पहुंच थी। वित्तीय बाधाओं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत के प्रवेश से लाए गए नियामक परिवर्तनों के कारण, सरकार केवल लक्षित आबादी के लिए आवश्यक संसाधनों को वितरित करने में सक्षम थी- जो सरकारी सहायता के योग्य थे।
- इसके परिणामस्वरूप सरकार ने बाद में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की। दूसरे शब्दों में, सरकार जरूरतमंदों को खाद्य सब्सिडी प्रदान करती है।
- इसके कारणों और विशेषताओं की विस्तृत श्रृंखला को देखते हुए, गरीबी को सटीक रूप से परिभाषित करना चुनौतीपूर्ण है। यह एक देश से दूसरे देश, शहरी से ग्रामीण आदि में भिन्न होता है। या इसे दूसरे तरीके से कहें तो गरीबी के कई अलग-अलग अर्थ होते हैं।
- हालांकि, यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि किसी को गरीब माना जाता है यदि उन्हें भोजन, कपड़े, रहने की जगह, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा इत्यादि जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में परेशानी होती है।
- खर्च करने की शक्ति: विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र गरीबी की गणना के लिए नाममात्र सापेक्ष आधार और समानता का उपयोग करते हैं।

- नतीजतन, गरीबी को परिप्रेक्ष्य के आधार पर अलग तरह से देखा जाता है।

भारत की गरीबी को कैसे मापा गया?

ब्रिटिश भारत की दुर्दशा का विश्लेषण:

- दादाभाई नौरोजी ने भारत के लिए पहला गरीबी अनुमान स्थापित किया, जिसे 1901 में अपनी पुस्तक "पाँवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया" में सार्वजनिक किया गया था।
- 1936 में, राष्ट्रीय योजना समिति ने औपनिवेशिक भारत में गरीबी के स्तर की गणना की। गरीबी की गणना के लिए आवास, भोजन और कपड़ों की लागतों को मिला दिया गया। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इस रणनीति का उपयोग किया। राष्ट्रीय योजना समिति के आकलन के अनुसार ब्रिटिश भारत की अर्थव्यवस्था भयानक स्थिति में थी।

स्वतंत्र भारत की गरीबी दर का अनुमान है:

- 1962 में, राष्ट्र के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया था।
- यह मूल्यांकन ग्रामीण भारत में कैलोरी की अनुमानित लागत और जीवित रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम कैलोरी पर आधारित था। यह दर्शाता है कि सामान्य मासिक गरीबी स्तर रु. 20, 1960-1961 में कीमतों के आधार पर



- अलग समिति: 1979 से पहले, एक व्यक्ति की आय का उपयोग उनकी गरीबी के स्तर को मापने के लिए किया जाता था। वार्डके अलग के नेतृत्व वाले एक समूह के अनुसार, गरीबी के स्तर की गणना 1979 में इस डेटा का उपयोग करके की गई थी कि आम जनता कितनी कैलोरी का उपभोग करती है। समिति के अनुसार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कैसे देखा जाता है, इसमें अंतर है। यदि कोई ग्रामीण निवासी प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम का उपभोग करता है, तो उसे बीपीएल माना जाता है। एक व्यक्ति को गरीबी में रहने वाला माना जाता है यदि वह शहरी वातावरण में प्रति दिन 2100 कैलोरी से कम लेता है। यह माना जाता है कि शहरवासियों को कम कैलोरी की आवश्यकता होती है क्योंकि वे ग्रामीण परिवेश की तुलना में कम शारीरिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। भारतीय गरीबी का स्तर शुरू में अलग समिति द्वारा स्थापित किया गया था।
- लकड़ावाला फॉर्मूला डीटी लकड़ावाला के नेतृत्व वाली लकड़ावाला समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह प्रति व्यक्ति घरेलू खर्च के लिए जिम्मेदार है। अलग और लकड़ावाला समितियों दोनों ने एक ही रणनीति का इस्तेमाल किया। हालाँकि, इसमें कुछ पूर्वापेक्षाएँ थीं जो बाद में नहीं थीं। अनुमान में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को ध्यान में रखा गया। इस समिति द्वारा सीपीआई-आईएल (औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) और सीपीआई-एएल (कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) का उपयोग करके गरीबी रेखा की स्थापना की गई थी। यह विधि गरीबों का आकलन करने के लिए पूर्ण न्यूनतम प्रति व्यक्ति घरेलू खर्च के औसत की गणना करती है। कोई भी व्यक्ति

जो ऐसे घर में रहता है जहाँ प्रति व्यक्ति खर्च देश के औसत से कम है, उसे बीपीएल माना जाता है। परिकलित मूल्य को तब गरीबी रेखा में जोड़ा जाता है। इस पद्धति का उपयोग करते हुए,

- योजना आयोग ने 2005 में सुरेश तेंदुलकर समिति की स्थापना की। इस समिति द्वारा दिए गए सुझाव आज भी उपयोग में हैं। यह सुझाव दिया गया था कि कैलोरी-आधारित दृष्टिकोण को छोड़ दिया जाए और उपयोगिताओं, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए मासिक लागतों को शामिल किया जाए। गरीबी को परिभाषित करने और उसका आकलन करने के लिए, इसने "गरीबी रेखा टोकरी" वाक्यांश गढ़ा। गरीबी रेखा की टोकरी का शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समान होना आवश्यक था। एक व्यक्ति को गरीबी में रहने वाला माना जाता है यदि उसके पास गरीबी की टोकरी में किसी भी चीज तक पहुंच नहीं है। यह दृष्टिकोण निर्धनता के अपने निर्धारण को जीवन यापन की लागत पर आधारित करता है। हालाँकि, अनुमान भयानक रूप से अपर्याप्त था, जिसने जनता को प्रभावित किया। परिणामस्वरूप, रंगराजन समिति की स्थापना की गई।
- रंगराजन समिति की स्थापना 2012 में हुई थी, और रंगराजन ने इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। यह कैलोरी के आधार पर गरीबी के आकलन का भी उपयोग करता है। इसकी सीमाएँ हैं क्योंकि इसने केवल न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखा है। यह आरामदायक रहने वाले क्वार्टरों की आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखता है।



- गरीबी रेखा के वर्तमान अनुमान: उपरोक्त परिस्थितियाँ दर्शाती हैं कि गरीबी रेखा का पता लगाना कितना चुनौतीपूर्ण है। भारत सरकार अभी भी देश के गरीबी के स्तर को निर्धारित करने के लिए एक सटीक प्रणाली बनाने में असमर्थ है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में 14 सदस्यीय कार्य समिति को यह मिशन दिया गया था। वे अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं और समस्या से निपटने के लिए एक नया, विशेष संगठन बनाने का सुझाव देते हैं।

भारत की गरीबी की जड़ क्या है?

- औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा शोषण: औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के जबरन गैर-औद्योगिकीकरण के कारण कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि हुई और वस्त्र और पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों के निर्यात में गिरावट आई। स्थानीय लोग स्थानीय रूप से निर्माण करने में असमर्थ थे क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सामान खरीदने के लिए मजबूर किया गया था। नतीजतन, एक उच्च बेरोजगारी दर है। उस समय भारतीयों की स्थिति बीमारियों, सूखे और अन्य कारकों से बदतर हो गई थी।
- मृत्यु दर में गिरावट और जन्म दर में वृद्धि के कारण तीव्र जनसंख्या वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद हो सकती है। हालांकि, मौजूदा उच्च बेरोजगारी दर और नौकरीपेशा लोगों पर बढ़ती निर्भरता के साथ, यह एक मुद्दा बनने लगा है। आर्थिक प्रगति को बनाए रखने के लिए, विशाल जनसंख्या को मानव पूंजी में बदलना होगा।
- प्राकृतिक आपदाएँ: बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भारतीय राज्य हैं जहाँ बीपीएल निवासियों का प्रतिशत सबसे अधिक है। यह इस तथ्य के कारण है कि इन राज्यों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का वर्चस्व है, उनका प्रतिनिधित्व कम है और वे प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। वहां होने वाली प्राकृतिक आपदाएं इन राज्यों की आर्थिक रूप से और कृषि के मामले में बढ़ने की क्षमता को सीमित करती हैं।
- असंगठित क्षेत्र की वृद्धि: असंगठित उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा प्रतिशत बनाते हैं। अब मजदूरों के शोषण का मामला सामने आया है। नौकरियों की मांग बढ़ी है, जिससे नौकरी की चिंता और भी बढ़ गई है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे खराब प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में से एक कृषि है। बढ़ते कर्ज और घटते उत्पादन के कारण किसानों का विरोध और आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। परिणामस्वरूप दीर्घकालिक गरीबी का उन पर प्रभाव पड़ेगा। अधिकांश भारतीय इस कम वेतन वाले क्षेत्र में कार्यरत हैं।
- निवेश: निवेश उपलब्ध नौकरियों के पूल का विस्तार करता है। इसे पूरा करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए खुला होना चाहिए। हालाँकि, भारत के कुछ क्षेत्र उग्रवाद, भ्रष्टाचार और अन्य समस्याओं के कारण प्रतिकूल बने हुए हैं।



- सामाजिक कारक: भारत के कुछ हिस्सों में, जाति संरचना, निरक्षरता दर, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के तहत, और सामाजिक मानक अभी भी प्रमुख हैं।
- कुशल श्रम की कमी: यदि ठीक से उपयोग किया जाए, तो लोग अर्थव्यवस्था के लिए एक संसाधन बन सकते हैं। यह वह जगह है जहाँ मानव पूंजी का उपयोग मदद कर सकता है। जनसंख्या साक्षरता पहल की गति थोड़ी मामूली है। कुछ आवेदकों को नौकरियों से खारिज कर दिया जाता है क्योंकि उनके पास आवश्यक क्षमताओं की कमी होती है। इसलिए बेरोजगारी और गरीबी है।
- भ्रष्टाचार : गरीबी कम करने के मामले में प्रशासन ने काफी प्रगति की है। हालांकि अभी भी राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। सत्ता के भ्रष्ट होने की स्थिति में गरीबी भी एक परिणाम है।
- संसाधन अपशिष्ट: भारत प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता वाला देश है, जिसका सावधानीपूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग करने पर लाभकारी हो सकता है।
- उद्यमी भावना की कमी: भारत विभिन्न आर्थिक उत्तेजक प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, कई जनजातियाँ अपनी समृद्ध रचनात्मक और सांस्कृतिक विरासत का उपयोग करके समृद्ध व्यवसाय के माध्यम से फल-फूल सकती हैं। हालांकि, उद्यमशीलता की भावना और नेतृत्व की कमी के कारण वे बर्बाद हो जाते हैं। भारतीय समाज में सबसे कमजोर समूहों में से एक अभी भी जनजातियाँ हैं।

- बुनियादी ढांचे की कमी के कारण जबरदस्त आर्थिक प्रगति के बावजूद भारत में अभी भी कई दूरस्थ क्षेत्र हैं। कई भारतीय गांवों में अभी भी बिजली जैसी आवश्यक सुविधाओं तक सीमित पहुंच है, जो उनके जीवन स्तर को कम करती है। यहां तक कि सड़कें और ट्रेनें भी नाकाफी हैं। पहुंच के कारणों से, वे अर्थव्यवस्था की मदद करने में असमर्थ हैं।

अभी क्या स्थिति है?

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी 2019 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, 2005-2006 और 2015-16 के बीच भारत की बहुआयामी गरीबी में 27.5% की कमी आई है। बहुआयामी गरीबी गरीबों का मूल्यांकन है जो न केवल उनकी आय के स्तर बल्कि उनके सामान्य स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति को भी ध्यान में रखता है।
- वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के अनुसार, लगभग 44 भारतीय हर मिनट अत्यधिक गरीबी से बच रहे हैं।
- 2011 तक दुनिया की कुल आबादी में भारतीयों की संख्या 21.9 प्रतिशत थी।
- अप्रैल 2021 तक, बेरोजगारी दर 7.1% है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि देश में बेरोजगारी और गरीबी का गहरा संबंध है। गरीबों के लाभ के लिए, हाल के वर्षों में बुनियादी ढांचा विकास गतिविधियों में विस्फोट हुआ है, जिसमें नई सड़कों का निर्माण और आवास विकास शामिल हैं। यह अधिक विदेशी निवेश को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- जनवरी 2020 के 4.3 प्रतिशत के अनुमान के विपरीत, 2020 में भारत की गरीबी दर में 9.7 प्रतिशत की अपेक्षित वृद्धि हुई है।



- अनुमानों के अनुसार, 2011 और 2019 के बीच भारत के 340 मिलियन वंचित नागरिक गिरकर 78 मिलियन हो गए।
- वर्ष 2020 तक संख्या में 75 मिलियन की वृद्धि हुई।
- लोगों को गरीब के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी दैनिक आय \$ 2 या उससे कम है।
- वैश्विक गरीबी में वृद्धि का लगभग 60% भारत को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) में प्रतिभागियों की संख्या में रिकॉर्ड दर से वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि गरीबों को रोजगार खोजने में कठिनाई हो रही थी।

मध्यम वर्ग:

- भविष्यवाणियों के मुताबिक, भारत का मध्यम वर्ग 2020 तक 3.2 करोड़ कम हो जाएगा।
- मध्यम वर्ग के लोग प्रतिदिन \$10 और \$20 के बीच, या रुपये के बीच कमाते हैं।
- यह संभव है कि मध्यम आय वर्ग लगभग 10 करोड़ से घटकर केवल 6.6 करोड़ रह गया हो।

कम आय वाला समूह:

- भारत में, अधिकांश लोगों के बारे में माना जाता है कि उनकी आय कम है।
- इस समूह की दैनिक जनसंख्या 119.7 करोड़ से घटकर 116.2 करोड़ हो गई, जिनमें से लगभग 3.5 करोड़ को गरीब माना गया।
- कम आय वाले लोगों की दैनिक आय रुपये से लेकर है। 150 से रु. 700.

विशेषाधिकार के साथ जनसंख्या:

- संपन्न आबादी लगभग 30% घटकर 1.8 करोड़ व्यक्ति रह गई।
- यदि कोई व्यक्ति रुपये से अधिक कमाता है। 1,500 एक दिन, उन्हें "अमीर" माना जाता है।

कारण:

- व्यवसाय बंद हो गए, लोगों की नौकरी चली गई, और महामारी से प्रेरित लॉकडाउन के परिणामस्वरूप राजस्व में कमी आई, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक गंभीर अवसाद में भेज दिया।

गरीबी की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वरोजगार स्वर्णजयंती ग्राम योजना:

- शुरुआत 1 अप्रैल, 1999 को हुई।
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास, मिलियन वेल्स योजना, ग्रामीण कारीगरों को बेहतर टूलकिट की आपूर्ति (एसआईटीआरए), ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण (टीआरवाईएसईएम), और गंगा कल्याण योजना सभी को एक कार्यक्रम में मिला दिया गया। (डीडब्ल्यूसीआरए)।
- इसका प्रमुख लक्ष्य लाभार्थियों को बीपीएल से बाहर लाना है।
- यह वंचित मूल के ग्रामीण निवासियों को सहायता प्रदान करता है जो स्वरोजगार करते हैं।
- राज्य और केंद्र के बीच पैसा 75:25 बांटा गया है।



- यह पहल क्लस्टरों में काम करके ग्रामीण गरीबों को समावेशी और कुशल सहायता प्रदान करने का प्रयास करती है।
- प्रशिक्षण देने, क्षमता निर्माण करने और राजस्व सृजित करने के लिए संपत्ति प्रदान करने के लिए, ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जाता है।
- 2011 तक कार्यक्रम का नया नाम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन था।
- इसे अंततः कम भाग्यशाली लोगों की सहायता के लिए दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के साथ जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त, यह योजना बेघर लोगों को सब्सिडी और आश्रय प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वेंडर मार्केटप्लेस बनाए जा रहे हैं।

एक स्थानीय विकास पहल:

- इस कार्यक्रम ने पिछले जवाहर रोजगार कार्यक्रम की जगह ले ली।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण लक्ष्य था जब इसे अप्रैल 1999 में शुरू किया गया था।

प्रधानमंत्री आवास योजना:

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और प्रधानमंत्री आवास योजना इसके दो मुख्य घटक (शहरी) हैं।
- इसकी शुरुआत पहली बार 2015 में हुई थी।
- यह सौभाग्य योजना और उज्ज्वला योजना (जो बीपीएल को एलपीजी देती है) के साथ-साथ टॉयलेट, पानी और पीने के पानी (बिजली) की सुविधाओं तक पहुंच जैसे कार्यक्रमों को एक साथ लाता है।

मनरेगा, 2005:

- यह ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की गारंटीकृत रोजगार प्रदान करता है।
- यदि उनकी वांछित नौकरी उपलब्ध नहीं है और वे 15 दिनों से अधिक समय से बेरोजगार हैं, तो उन्हें बेरोजगारी मुआवजा मिलेगा।
- नतीजतन, सरकार को जवाबदेह ठहराया जाता है और ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार की संभावनाएं उपलब्ध होती हैं।
- ग्रामीण संपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के बदले खाद्य पहल रोजगार योजना की तुलना में अधिक संसाधन और सहायता प्रदान करती है। योजना आयोग ने इस पहल में पीछे रहने वाले 150 जिलों को सूचीबद्ध किया। उन्हें उनके प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया। रोजगार और खाद्य सुरक्षा के लिए सामाजिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना:

- यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे उद्योग की जरूरतों के साथ अपने कौशल सेट को संरेखित करने में व्यक्तियों की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- राष्ट्र कौशल विकास निगम इस कार्यक्रम (एनएसवीसी) की देखरेख करता है।
- सरकारी सहायता का उपयोग प्रशिक्षण और मूल्यांकन लागतों को कवर करने के लिए किया जाता है।
- राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा और उद्योग मानक इस कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराए गए प्रशिक्षण की नींव के रूप में कार्य करते हैं।
- हाई स्कूल और कॉलेज से स्नातक और ड्रॉपआउट दोनों प्रासकर्ता हैं।



- तेलंगाना में रयथु बंधु योजना को उन सभी जमींदारों की पेशकश करने के लिए रखा गया था जो किसानों को रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करते थे। 4000 प्रति एकड़ प्रति सीजन।
- किसान प्रधान, सम्मान, निकोल इस प्रयास का उद्देश्य सभी भूमिधारक किसानों को कार्यशील पूंजी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह भारतीय किसानों के लिए एक सार्वभौमिक बुनियादी आय की अवधारणा को बढ़ावा देता है। और अधिक जानें।

महामारी के बाद की पहल:

- उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहनों के लिए कार्यक्रम
- अभियान गरीब कल्याण रोजगार

आगे कैसे जारी रखें:

- सरकार को कल्याणकारी योजनाओं को चलाने वाले कई संगठनों से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करनी चाहिए।
- बुनियादी ढांचे और प्रतिभा विकास पर सर्वोच्च ध्यान देना महत्वपूर्ण है।
- पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ा है।
- लक्ष्य समूह की सहायता के लिए गरीबी को परिभाषित करने में सक्षम न होने के मुद्दे को निश्चित किया जाना चाहिए।
- जरूरतमंदों को प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण देना एक त्वरित समाधान है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम को ध्यान में रखना जरूरी है।
- ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए सरकार को कृषि में निवेश करना चाहिए। मुद्दे केवल सब्सिडी द्वारा अस्थायी रूप से तय किए जाते हैं। किसानों को हर मौसम में खेती

करने में सक्षम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास भी आवश्यक है।

- विकास जो रोजगार को पहले रखता है आज अर्थव्यवस्था का विस्तार करने के लिए, अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों का समर्थन करें जो बहुत अधिक श्रम की मांग करते हैं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवाएं प्रभावी ढंग से प्रदान की जाती हैं, भ्रष्टाचार को कम करें।
- लोगों को गरीबी की स्थिति में कैद रखने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण, कौशल और संसाधन देकर लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालने में मदद करने के लिए बनाए गए समग्र, बहुआयामी हस्तक्षेपों के माध्यम से, गरीब परिवार पर्याप्त रूप से लचीला बनना सीख सकते हैं। महत्वपूर्ण झटके झेलते हैं। पशुधन जैसे संसाधनों के अलावा, सरकार को इन संसाधनों को आकर्षक बनाने के लिए आर्थिक और वित्तीय कौशल, आशावाद और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक-एक कोचिंग, परिवारों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और अन्य चीजों में प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।



2. भारत में सभी मुफ्त सुविधाओं के बारे में:

फ्रीबीज क्या दर्शाता है:

- आम जनता का समर्थन जीतने के लिए, राजनीतिक दल मुफ्त बिजली और पानी, महिलाओं, दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और बेरोजगार लोगों के लिए मासिक भत्ते के साथ-साथ लैपटॉप और सेलफोन जैसी तकनीक प्रदान करने का वादा करते हैं।
- ऋण माफी, मुफ्त बिजली, मोटरसाइकिल, लैपटॉप, टीवी और अन्य सामान जैसे मुफ्त कुछ ऐसे हैं जो राज्यों के पास प्रदान करने का इतिहास है।
- लोकलुभावन दबाव के जवाब में या चुनावों को ध्यान में रखते हुए कुछ संदिग्ध खर्च के फैसले किए जा सकते हैं।
- हालाँकि, यह देखते हुए कि पिछले 30 वर्षों में असमानता बढ़ी है, सब्सिडी के रूप में आबादी को किसी प्रकार की राहत प्रदान करना न केवल उचित हो सकता है, बल्कि वास्तव में आवश्यक भी हो सकता है यदि हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था का विस्तार जारी रहे।

मुफ्त चीजों का क्या औचित्य है?

- विकास को प्रोत्साहित करता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार गारंटी कार्यक्रम, शिक्षा के लिए समर्थन, और स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि, विशेष रूप से महामारी के दौरान सकारात्मक समग्र प्रभाव वाले व्यय के कुछ उदाहरण हैं।

- ये दोनों किसी भी विकास रणनीति के आवश्यक घटक हैं क्योंकि ये अधिक उत्पादन करने की जनसंख्या की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं और अधिक मजबूत और स्वस्थ श्रम शक्ति के विकास में योगदान करते हैं।
- स्वास्थ्य और शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च बराबर है।
- उद्योग की बिक्री में वृद्धि तमिलनाडु और बिहार जैसे राज्यों में सिलाई मशीन, साड़ी और साइकिल आमतौर पर महिलाओं को सौंपी जाती है; फिर भी, इन खरीदों का भुगतान बजटीय निधि से किया जाता है, जिससे उद्योग की बिक्री में वृद्धि होती है।
- उसी विनिर्माण को देखते हुए, इसे एक अनावश्यक निवेश के विपरीत आपूर्ति उद्योग के लिए एक लाभ के रूप में देखा जा सकता है।
- अपेक्षाओं से अधिक के लिए महत्वपूर्ण: भारत जैसे देशों में, जहां प्रत्येक राज्य में विकास के अलग-अलग स्तर हैं, लोगों को उम्मीद है कि ये मुफ्त-उपहार वादे चुनाव के करीब आने पर पूरा करने में मदद करेंगे।
- जब पड़ोसी या अन्य राज्यों (विभिन्न सत्तारूढ़ दलों के साथ) के निवासियों को मुफ्त उपहार मिलते हैं, तो अक्सर तुलना की अपेक्षा की जाती है।
- कम विकसित राष्ट्रों को सहायता: गरीबी और विकास के निम्न स्तर में रहने वाली आबादी के उच्च प्रतिशत वाले राज्यों में, इस तरह के मुफ्त की जरूरत या मांग-आधारित हो जाते हैं, और लोगों को अपने स्वयं के उत्थान के लिए इस तरह की सब्सिडी प्रदान करना महत्वपूर्ण है।



मुफ्त चीजों में क्या कमियां हैं?

- फ्रीबी राजनीति ने खर्च की प्राथमिकताओं को बदल दिया, मुफ्त में व्यापक आर्थिक स्थिरता की नींव को खतरे में डाल दिया, और अधिकांश खर्च अभी भी किसी न किसी तरह की सब्सिडी के लिए आवंटित किया गया है।
- राज्यों की वित्तीय भलाई पर प्रभाव चीजों को मुफ्त में देने से अंततः सार्वजनिक परिसर पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अधिकांश भारतीय राज्यों की वित्तीय स्थिति कमजोर होती है और राजस्व के मामले में अक्सर सीमित संसाधन होते हैं।
- राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब हो जाएगी और यदि वे प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक लक्ष्यों पर पैसा खर्च करना जारी रखते हैं तो राजकोषीय लापरवाही नियंत्रण में आ जाएगी।
- राज्य की उधारी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) नियमों द्वारा प्रतिबंधित है, और किसी भी विचलन के लिए संघीय सरकार और केंद्रीय बैंक दोनों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। राज्यों को अनुमति से अधिक कर्ज लेने की अनुमति नहीं है।
- इसलिए, राज्य अपना पैसा खर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं, हालांकि वे फिट देखते हैं, हालांकि आमतौर पर उन्हें अपने अनुमत घाटे से अधिक जाने की अनुमति नहीं है।
- चुनाव से पहले जनता के पैसे से संभव हुआ तर्कहीन मुफ्त उपहारों के वितरण का विरोध किया जाता है क्योंकि यह मतदाताओं को गलत तरीके से राजी करने और सत्ता के संतुलन को बिगाड़ने से चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को कलंकित करता है।

- यह बेईमान व्यवहार है जो मतदाताओं से समर्थकों को खरीदने जैसा है।
- पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए: असीमित मात्रा में मुफ्त पानी, बिजली, या अन्य उपभोग्य सामग्रियों की पेशकश करने से अक्षय ऊर्जा, पर्यावरण के अनुकूल विकास और उन्नत सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में निवेश से धन की निकासी होती है।
- इसके अतिरिक्त, जब कुछ "मुफ्त" प्रदान किया जाता है, तो लोगों के लिए इसका अत्यधिक उपयोग करना (प्रक्रिया में संसाधनों को बर्बाद करना) आम बात है।
- फ्रीबीज का भविष्य के उत्पादन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे प्रतिस्पर्धी और कुशल बुनियादी ढांचे को समाप्त कर देते हैं जो विनिर्माण क्षेत्र में उच्च-कारक दक्षता का समर्थन करते हैं, इस क्षेत्र की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करते हैं।
- उपहारों के बदले में ऋण छूट देने से अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं, जिसमें संपूर्ण क्रेडिट संस्कृति का उन्मूलन और इतने सारे किसान कर्ज में डूबे रहने के छिपे हुए अंतर्निहित कारण शामिल हैं।

अगले कदम:

- फ्रीबीज की सही कीमत को समझना: जबकि फ्रीबीज अल्पावधि में एक अच्छे सौदे की तरह लग सकता है, अर्थव्यवस्था, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक सामंजस्य पर उनका वास्तविक प्रभाव कहीं अधिक है।



- इसके बजाय, हमें लोकतांत्रिक, प्रबुद्ध संघवादी प्रयोगशालाओं के माध्यम से एक दक्षता दौड़ का पीछा करना चाहिए, जहां अलग-अलग राज्य अपनी शक्ति का उपयोग वैश्विक मुद्दों के नए जवाब देने के लिए करते हैं जिन्हें अन्य राष्ट्र अपना सकते हैं।
- मांग-आधारित मुफ्त सुविधाएं जो काम करती हैं: भारत में अभी भी बहुत से लोग गरीबी में जी रहे हैं, एक विशाल देश। देश की विकास योजना में पूरी आबादी को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- मुफ्त या सब्सिडी जो विवेकपूर्ण तरीके से पेश की जाती हैं, आसानी से राज्य के बजट में समायोजित की जाती हैं, और लीवरेज के रूप में उपयोग की जा सकती हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता है।
- एक आदर्श दुनिया में, सरकार द्वारा खर्च किए गए कुछ धन को समग्र रूप से बेहतर संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए अलग रखा जाएगा।
- फ्रीबीज से सब्सिडी को अलग करना: फ्रीबीज के वित्तीय प्रभाव को समझना और वे टैक्स प्राप्ति से कैसे संबंधित हैं, यह महत्वपूर्ण है।
- सब्सिडी वे लाभ हैं जो उचित हैं, उचित रूप से लक्षित हैं, और मांग का परिणाम हैं; फ्रीबीज को सब्सिडी से अलग किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों की सहायता के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को धन देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ऐसा करने से राज्य या संघीय संसाधनों पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

Guru Deekshaa IAS is happy to announce first ever kannada current affairs magazine for kannada medium aspirants of Karnataka. The three important thumb rules for any competitive exam are



Vijay Kumar G

Founder and Director
Guru Deekshaa IAS

-  First-NCERT/STATE syllabus books which helps to develop your understanding on the subjects
-  Second-Daily current affairs helped to build your further understanding of the events related to your examination, Apart from knowledge it build the personality of an individual which brings in confidence to face any examination.
-  Third-Practice previous year question papers and mock test available in the market to train your mind as per the requirement of the examination.

Thousand miles of journey starts with single step, We at Guru Deekshaa have taken this first step towards empowering you to prepare for civil for services. Now its your turn to start preparation and achieve your dream of becoming IAS/IPS.

CALL US FOR MORE DETAILS

 **76 76 74 98 77**

JOIN OFFICIAL TELEGRAM FOR MATERIAL AND UPDATES

 @GURU_DEEKSHAAIAS



FOLLOW OUR INSTAGRAM FOR DAILY UPDATES

 GURUDEEKSHAA

